Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 76-2017/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MAY 4, 2017 (VAISAKHA 13, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th May, 2017

No. 27-HLA of 2017.— The Haryana Legislative Assembly Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2017, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 27- HLA of 2017

THE HARYANA SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL, 2017

A

BILL

further to amend the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1st April, 2016.

Amendment of section 3 of Haryana Act 3 of 1970.

2. In sub-section (1) of section 3 of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970 (hereinafter called the principal Act), for the words "fifty thousand rupees", the words "sixty thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 5A of Haryana Act 3 of 1970.

3. In section 5A of the principal Act, for the words "two thousand rupees", the words "twenty thousand rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present, Ministers and Ministers of State are being paid Salary @ ₹ 50,000/- per month and Office Allowance @ ₹ 2,000/- per month as per Section 3(1) and Section 5(A), respectively, of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

Keeping in view the rise in the cost of living as well as office expenses, the Government has decided to increase the salary of Ministers and Ministers of State from ₹ 50,000/- per month to ₹ 60,000/- per month and the Office Allowance from ₹ 2,000/- per month to ₹ 20,000/- per month.

RAM BILAS SHARMA,
Parliamentary Affairs Minister,
Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the Introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 4th May, 2017.

R. K. NANDAL,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed increase in Salary & Office Allowance of Ministers and Ministers of State will entail an extra expenditure of approximately ₹ 47,54,000/- (₹ Forty seven lacs fifty four thousand only) per year from the State Exchequer.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2017 का विधेयक संख्या–27 एच०एल०ए०

हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2017

हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1970,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2016 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1970 के हरियाणा अधिनियम 3 की धारा 3 का संशोधन।

2. हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1970 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) में, ''पचास हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर, ''साठ हजार रुपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1970 के हरियाणा अधिनियम 3 की धारा 5क का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5क में, ''दो हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर, ''बीस हजार रूपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

वर्तमान में हरियाणा मंत्री तथा राज्य मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के अनुसार मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को 50,000/–रु0 प्रति माह वेतन दिया जा रहा है और धारा 5(क) के अनुसार कार्यालय भत्ता 2,000/– रु0 प्रति माह दिया जा रहा है

जीवनोपयोगी वस्तुओं व कार्यालय के खर्चों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत सरकार ने निर्णय लिया है कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों का वेतन 50,000/–रु0 प्रति माह से बढ़ाकर 60,000/–रु0 प्रति माह कर दिया जाए तथा कार्यालय भत्ता 2,000/– रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20,000/– रुपये प्रति माह कर दिया जाए।

राम बिलास शर्मा,
संसदीय कार्य मंत्री,
हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 4 मई, 2017.

आर० के० नांदल,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा के मंत्रियो तथा राज्य मंत्रियों के वेतन और कार्यालय भत्ता की प्रस्तावित बढ़ोतरी करने पर राजकोष पर लगभग ₹ 47,54,000/– (सैंतालिस लाख चव्वन हजार रुपये) प्रति वर्ष अतिरिक्त खर्चा आएगा।

55271—H.V.S.—H.G.P., Chd.